

संसद में वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर वोट करेगा

हालांकि संभावना है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत होने के कारण यह बिल लोकसभा व राज्यसभा में पारित हो जाएगा

—रेणु मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। “इंडिया” गठबंधन में शामिल सभी विपक्षी दल सामूहिक रूप से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ वोट देंगे। यह विधेयक कल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये मंगलवार शाम को इंडिया ब्लॉक के सभी विपक्षी दलों की मीटिंग हुई तथा यह तय हुआ कि ये सभी दल पूरी चर्चा में भाग लेंगे तथा उसके बाद सभी सामूहिक रूप से विधेयक के विरुद्ध वोट देंगे।

अगले दिन यह विधेयक राज्यसभा में रखा जाएगा। यह तो तय सा है कि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाएगा, क्योंकि तेलुगूदेशम पार्टी (टीडीपी) तथा जनता दल (यू) इसका समर्थन करेंगे।

पहले इन्होंने इस विधेयक का विरोध किया था तथा जेपीसी की माँग

■ भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर संसद में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया है।

■ सत्तारूढ़ एन.डी.ए. के घटक दल (यू) और तेलुगूदेशम पहले वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ थे पर अब वे बिल के पक्ष में वोट करेंगे और उन्होंने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है।

■ ज्ञातव्य है कि जद (यू) और तेलुगूदेशम के विरोध पर ही वक्फ विधेयक जेपीसी को भेजा गया था और इन दलों द्वारा प्रस्तावित संशोधन सरकार ने स्वीकार कर लिए हैं।

■ इंडिया ब्लॉक के भी सभी दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी की है। विपक्ष पूरी ताकत से सरकार का विरोध करेगा।

■ बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और सरकार उससे पहले वक्फ बोर्ड बिल पारित करा लेना चाहती है।

की थी तथा सरकार, अपने मित्र दलों के दबाव पर, जेपीसी के लिये सहमत भी

हो गई थी।

टीडीपी तथा जेडी (यू) दोनों ही दलों ने, तीन पंक्ति का व्हिप जारी करके अपने सभी सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने तथा वक्फ विधेयक पर सरकार का समर्थन करने के लिए कहा है।

वक्फ विधेयक को पारित करने में टीडीपी के समर्थन के बदले में, सरकार उसके तीन संशोधनों पर सहमत हो गई है।

विपक्ष ने भी विधेयक का विरोध करने के लिये अपने सदस्यों के लिये व्हिप जारी किये हैं तथा ऐसी आशा की जा रही है कि विपक्ष पूरी ताकत से सरकार का मुकाबला करेगा तथा मोदी सरकार के हिन्दू-मुस्लिम एजेंडे की बखिया उधेड़ेगा।

बजट सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होना है तथा सरकार की कोशिश है कि संसद के अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने से पहले, वक्फ विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाये।

मुख्यमंत्री भजनलाल की राज्य कर्मचारियों को सौगात

जयपुर, 1 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्षीय कार्यक्रम संवत् (2082) एवं नवीन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अवसर पर राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की सौगात दी है। पेंशनर्स को भी महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि देय होगी। उल्लेखनीय है कि गत शुरुवार को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के डीए में बढोत्तरी की गई थी। इस बढोत्तरी के बाद पहले कार्यदिवस पर ही मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिना देरी किए राज्य में भी केन्द्र सरकार के

■ राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाने के आदेश दिए।

कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता तथा महंगाई राहत में वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। अब प्रदेश में सातवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से 53 प्रतिशत से बढाकर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता अथवा महंगाई राहत देय होगी। इस निर्णय का लाभ लगभग 8 लाख कर्मचारियों एवं 4.40 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। पंचायत समिति (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘जिनके घर गिराए हैं उन्हें 6 सप्ताह में दस लाख रूपए हर्जाना दिया जाए’

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में लोगों के घर गिराए जाने को अमानवीय कृत्य बताते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया

—डॉ. सतीश मिश्रा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय आज योगी आदित्यनाथ सरकार तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण पर भारी नाराजगी जताई और शहर में घरों को गिराये जाने को “अमानवीय और अवैध” करार दिया। जस्टिस अभय एस. ओका तथा उज्जल भूयान की बेंच ने मकान तोड़ने को कार्यवाही को मनमानी और दादागिरी पूर्ण बताते हुए कहा कि “देश में कानून का शासन” है और नागरिकों के घर इस तरह नहीं दहाये जा सकते।

बेंच ने कहा, “इस घटना ने हमारी अन्तरात्मा को झकझोर दिया है। “आश्रय का अधिकार” (राइट टु शैल्टर) तथा “कानून की उचित प्रक्रिया” जैसी भी कोई चीज होती है।” इसलिये शीर्ष अदालत ने प्राधिकरण को निर्देश दिये कि जिनके

■ जस्टिस अभय एस. ओका और उज्जल भूयान की बेंच ने प्रयागराज में दादागिरी से मकान तोड़े जाने पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि देश में कानून का राज है और “आश्रय स्थल का अधिकार” भी कोई चीज है।

■ सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता, जलिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद तथा अन्य लोग, जिनके घर तोड़े हैं, की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि इन घटनाओं ने हमारी अन्तरात्मा को हिला दिया है।

भी मकान तोड़े हैं उन मकान मालिकों को वह छः सप्ताह के अन्दर 10 लाख रु. का हर्जाना दें।

शीर्ष अदालत एडवोकेट जलिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद तथा अन्य की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिनके मकान गिरा दिये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी प्रयागराज में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना की गई ध्वस्तीकरण की

कार्यवाही को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को जबरदस्त डाढ़ लगाई थी, तथा कहा था कि इससे “स्तब्धकारी एवं गलत संकेत” जाता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने गलतफहमी में मकान दहा दिये थे, उसने ऐसा लगा कि वह जमीन अपराधी-राजनेता अतीक अहमद की है, जो 2023 में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका था।

तमिलनाडु भाजपा में कौन लेगा अन्नामलाई की जगह?

तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में तीन नाम सबसे आगे हैं

—लक्ष्मण वैकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 1 अप्रैल। तमिलनाडु भाजपा भारी परेशानी में है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि पार्टी नेतृत्व प्रदेश पार्टी अध्यक्ष को बदलने पर विचार कर रहा है। अन्नामलाई के विकल्प के रूप में तीन नाम चर्चा में हैं।

चर्चा है कि 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए अन्नाद्रमुक से गठबंधन की खातिर अन्नामलाई को हटाया जा रहा है। इस पद के लिए तेलंगाना की राज्यपाल और तमिलनाडु भाजपा की पूर्व अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन, तिरुनेलवेली की विधायक नैना नागेन्द्रन और थेवर समुदाय के कदावर नेता और सांसद एल. मुरुगन प्रमुख हैं।

असल में अन्नाद्रमुक ने भाजपा के सामने गठबंधन के लिए अन्नामलाई को हटाने की पूर्व शर्त रखी है। अन्नाद्रमुक ने लोकसभा चुनावों से पहले अन्नामलाई के व्यवहार के कारण भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया था। तब ऐसा लग रहा था मानो भाजपा गठबंधन तोड़ना चाहती थी और

■ पहले नम्बर पर हैं, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, जो पूर्व में भी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं।

■ इसके बाद तिरुनेलवेली की विधायक नैना नागेन्द्रन और थेवर जाति के कदावर नेता सांसद एल. मुरुगन का नाम चर्चा में हैं।

■ अब यह एकदम साफ है कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलाई के दिन पूरे हो चुके हैं। असल में अन्नाद्रमुक ने अन्नामलाई को हटाने की शर्त रख दी थी। भाजपा नेतृत्व ने अन्नाद्रमुक नेतृत्व को मनाने की बहुत कोशिश की, पर, पलानीस्वामी टस से मस नहीं हुए।

तमिलनाडु में अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है। अन्नामलाई अन्नाद्रमुक के नेताओं खासकर जयललिता के खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे थे। अन्नाद्रमुक के प्रमुख ई. पलानीस्वामी इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व ने उन्होंने मनाने की बहुत कोशिश की पर पलानीस्वामी नहीं माने। अभी भी उनकी

यही शर्त थी कि अगर अन्नामलाई रहे तो गठबंधन नहीं होगा। अन्नाद्रमुक के प्रवक्ता कोवाई सत्यन ने एक निजी टीवी चैनल से वार्ता में बताया कि जहां तक तमिलनाडु में गठबंधन का सवाल है अन्नाद्रमुक का ही पलड़ा भारी रहेगा। पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का नेता कौन होगा इसका निर्णय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्य राज्यों के दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

जयपुर, 1 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में प्रदेश से बाहर का दिव्यांग प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपौठ ने यह आदेश राहुल कुमार सहित करीब एक

■ हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 के एक मामले में सुनवाई करते हुए इन अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के आदेश दिए।

दर्जन अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सेनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 में अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ताओं ने सामान्य दिव्यांग वर्ग में आवेदन किया था। तथापि, उनका यह कहते हुए चयन नहीं किया गया कि उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रदेश से बाहर का है। इसको चुनौती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनस ने अपनी हाल की टिप्पणियों में, अपने देश को भारत के “लेण्ड लॉकड” (भूमि से घिरे हुये) पूर्वोत्तर राज्यों के लिये महासागर का “एकमात्र अभिभावक/संरक्षक” बताया है। उन्होंने चीन को बांग्लादेश में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाने के लिये आमंत्रित किया है। मुहम्मद यूनस की उक्त टिप्पणी और चीन को दिये गये आमंत्रण का भारत में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है।

अपनी हाल ही चीन यात्रा के दौरान, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख ने चीन से उनके देश (बांग्लादेश) में निवेश करने का अनुरोध किया था तथा कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का लेण्डलॉकड होना एक अवसर सिद्ध हो सकता है। यूनस ने कथित रूप से कहा कि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य लेण्डलॉकड हैं। उनके पास महासागर तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है। (इसलिये) महासागर के एकमात्र संरक्षक हम ही हैं। इससे एक बहुत बड़ी संभावना (का द्वार) खुलता है। इससे चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है।”

■ बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनस ने कहा, भारत के पूर्वोत्तर राज्य “लेण्ड लॉकड” अर्थात् भूमि से घिरे हुए हैं, उनके पास समुद्र तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। इसलिए समुद्र के संरक्षक हम हैं।

■ यूनस के इस बयान को लेकर भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों व विभिन्न दलों ने तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भारी विरोध जताया।

■ असल में पूर्वोत्तर राज्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक) के जरिए शेष भारत से जुड़े हुए हैं। यह नेपाल व बांग्लादेश के बीच का संकड़ा मार्ग है। चीन और भूटान इसके काफी समीप हैं, इसलिए भारी चिंता जताई जा रही है।

यूनस के इस बयान से भारत में सुरक्षा-संबंधी चिन्ताएं पैदा हो गई हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “बांग्लादेश, भारत को घेरने के लिये चीन को आमंत्रित कर रहा है। यह एक खतरनाक स्थिति है। भारत सरकार मणिपुर पर ध्यान नहीं दे रही है तथा अरुणाचल में चीन ने गाँव बसा ही दिये हैं। हमारी विदेश नीति इतनी करुणाजनक एवं दयनीय है कि जिस देश को अस्तित्व में आने के लिये भारत ने मदद की थी, वही आज हमारे खिलाफ लामबंदी कर रहा है।” शिव सेना (यूबीटी) नेता प्रियंका

चतुर्वेदी ने इसे एक ऐसी “खतरनाक स्थिति” बताया है, जो भारत की रक्षा-सुरक्षा से जुड़ी हुई है।

भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य आज सिलगुड़ी कॉरिडोर, जिसे “चिकन्स नैक” भी कहा जाता है, के जरिए शेष भारत से जुड़े हुये हैं। यह नेपाल और बांग्लादेश के बीच, जमीन की एक सँकरी सी पट्टी है तथा भूटान और चीन इस कॉरिडोर से कुछ सौ किलोमीटर दूर ही हैं।

यूनस के इस ताजा बयान से उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री बड़े उत्तेजित हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमन्त बिस्वा

सरमा ने पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने के अन्य ऐसे वैकल्पिक रास्ते तलाश करने की आवश्यकता पर जोर दिया है जो सिलगुड़ी कॉरिडोर से नहीं गुजरते हों। सरमा ने कहा कि यूनस का यह बयान भारत के सिलगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नैक कॉरिडोर) से जुड़ी “स्थायी रूप से असुरक्षित स्थिति (पर्सिस्टेंट वल्नेरैबिलिटी नैटिव) को दर्शा रहा है। उन्होंने कहा, “हमें वैकल्पिक रास्ते तलाशने ही होंगे, भले ही इस कार्य में इंजीनियरिंग-संबंधी जबरदस्त चुनौतियाँ सामने आयें।”

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बोरिन सिंह ने कहा कि यह तो स्पष्ट है कि यूनस बांग्लादेश की भू-राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए पूर्वोत्तर को एक “राजनीतिक बंधक” (स्ट्रैटेजिक पॉन) के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यूनस से आग्रह किया कि वे “अविवेकी बयान” न दें, क्योंकि इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

जयपुर, 1 अप्रैल। पाँचसौ मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सूरज बैरवा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर साठ हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जगमोहन अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं

■ पाँचसौ मामलों की विशेष अदालत ने कहा, अभियुक्त युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है, उस पर नरमी नहीं बरती जा सकती।

अपनाया जा सकता। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 28 जून, 2021 को वह वैवाहिक समारोह में करीली गया हुआ था और उसकी पत्नी काम करने घर से बाहर गई थी। शाम को पत्नी के घर आने पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो बाघों को रैस्क्यू कर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा

रायसेन/भोपाल, 01 अप्रैल। वन विभाग भोपाल एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की रैस्क्यू टीम, पशु चिकित्सकों एवं स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सहयोग से रायसेन जिले के भोजपुर वन क्षेत्र से दो बाघों को रैस्क्यू किया गया। रैस्क्यू के उपरांत दोनों टाइगर्स का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित ढंग से

■ मध्यप्रदेश में रायसेन जिले के भोजपुर वन क्षेत्र से रैस्क्यू किए गए टाइगर्स को लेकर प्रशासन को कई शिकायतें मिली थीं।

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भेजा गया। भोजपुर से लगे हुए वन क्षेत्र बीट भोजपुर में भोजपुर-इमलिया मार्ग पर एक माह से दो टाइगर्स का लगातार विचरण बना हुआ था। इन टाइगरों ने 5 मवेशियों का शिकार किया था। टाइगर के विचरण के कारण ग्रामीण असुरक्षित महसूस कर रहे थे। टाइगरों का खेतों में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

—लक्ष्मण वैकट कुची—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—

नई दिल्ली, 1 अप्रैल। इलैक्टोरल सर्वे और ओपीनियन पोलस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, खासतौर से इस समय जो एजेण्डा इन मीडिया कवायदों को प्रेरित कर रहे हैं उसे देखते हुए और तमिलनाडु सरकार के प्रदर्शन और मौजूदा राजनैतिक हालात पर हुए सर्वे को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

लेकिन सी वोटर, जो कि नियमित रूप से जनता की राय को ट्रैक करता रहता है, ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पूर्व करवाए गए अपने सर्वे में पाया है कि आगामी चुनावों में मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन काफी आगे हैं और जनता की राय पूछे जाने पर जनता ने उन्हें पहली पसंद बताया।

‘27 प्रतिशत मतदाता स्टालिन को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं’

सी वोटर सर्वे में यह भी खुलासा हुआ कि सुपर स्टार विजय का राजनीति में प्रवेश स्टालिन के लिए परेशानी पैदा कर सकता है

■ सी वोटर सर्वे के अनुसार, 27 प्रतिशत वोट के साथ स्टालिन अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों, ई. पलानीस्वामी और अन्नामलाई से काफी आगे हैं, जिन्हें दस-दस प्रतिशत वोट मिले हैं, पर, विजय 18 प्रतिशत वोट लेकर स्टालिन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

■ हालांकि, द्रमुक इस बात से खुश है कि जनता ने द्रमुक व स्टालिन के नेतृत्व में भरोसा जताया है, पर, युवा वर्ग में एक्टर विजय की अपील को अनदेखा नहीं किया जा सकता, खासकर “एटी इकम्बर्सी” फैक्टर को देखते हुए।

■ सर्वे में 15 प्रतिशत वोटर्स ने द्रमुक सरकार के काम काज पर पूर्ण संतोष, 36 प्रतिशत ने कुछ हद तक संतोष जताया, पर, 25 प्रतिशत ने असंतोष जाहिर किया और 24 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी। यह 49 प्रतिशत वोटर्स द्रमुक की टाइट का प्रमुख कारण है।

■ द्रमुक के लिए अभी तक राहत की बात यही है कि विपक्ष बंटता हुआ है। पर, अगर अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन, जिसके गंभीर प्रयास हो रहे हैं, हो जाता है तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री पद के लिए 27 प्रतिशत लोगों ने स्टालिन को प्राथकता दी वहीं भाजपा के अन्नामलाई और अन्नाद्रमुक के ई. पलानीस्वामी को दस-दस प्रतिशत लोगों ने अपनी पसंद बताया।

सी वोटर सर्वे ने बताया कि एक्टर विजय जो हाल ही में राजनीति में आए हैं, की पार्टी टीवी के शेष विपक्ष से आगे है, उन्हें 18 प्रतिशत लोगों ने अपना समर्थन दिया। एक तरह से यह नवीनतम सर्वे त्रिकोणात्मक संघर्ष का संकेत देता है पर इसमें द्रमुक का पलड़ा भारी है बशर्ते अन्नाद्रमुक और भाजपा का गठबंधन हो जाए, अन्यथा चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, जिससे द्रमुक के जीतने की संभावना और बढ़ जाती है। सर्वे को लेकर द्रमुक की खुशी का सबसे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है।

शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाए जाने में सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस हेतु राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कॉन्फ्रेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों की आय

बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण की घोषणा की गई है।

शर्मा ने सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं के भण्डारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्रामसेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों का योजनावद्ध ढंग से भण्डारण सुनिश्चित हो, ताकि इनका अधिकतम उपयोग लिया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के 1 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बजट 2025-26 में इन परिवारों की

■ 'सहकार से समृद्धि की भावना के साथ कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता'

संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार कर दी गई है। साथ ही, इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर आगामी वर्ष से 9 हजार प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य सहकारी ऋण विक्रय संघ लि0 की ओर से खरीफ सीजन 2024 में दलहन और तिलहन जैसे मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन की 4 हजार 700 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की गई, जिसमें मूंगफली की 4 लाख 38 हजार 800 मेट्रिक टन से भी अधिक की रिकॉर्ड खरीद की गई। साथ ही, रबी सीजन 2025-26 के लिए सरसों और चने की खरीद हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पर्याप्त प्रचार-प्रसार कर किसानों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए। पात्र किसानों की सहकारी बैंकों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों और ग्रामीणों के अधिक से अधिक बचत खाते सहकारी बैंकों में खुलें।

समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने विभाग की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है।

बैठक में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, शासन सचिव पशुपालन समित शर्मा, प्रबंध निदेशक राजफेड टीकम चन्द बोहरा, प्रबंध निदेशक आरएसएलडीबी जितेन्द्र

प्रसाद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

416 महिला पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति के आदेश

जयपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय समीकित बाल विकास सेवाएं द्वारा 416 महिला पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग का सुदृढीकरण किया जा रहा है। विभाग में कार्यों की कमी नहीं होने से कार्य सुगमता से होगा। जिससे महिला एवं बाल विकास की योजनाओं से आमजन सरलता और सुगमता से लाभान्वित हो सकेगा। निदेशक आईसीडीएस ओ पी बुनकर ने बताया कि विभाग में 416 कार्मिकों को पोस्टिंग मिली है। जिसमें से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटे से 216 कार्यकर्ताओं की महिला पर्यवेक्षक के रूप में भर्ती की गई है।



भगवान महावीर स्वामी के 2624 वें जन्म कल्याणक महोत्सव (महावीर जयंती महोत्सव) के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान जैन सभा जयपुर के तत्वावधान में जयपुर में 10 अप्रैल को आयोजित होने वाले महावीर जयंती समारोह के बहुरंगीय पोस्टर का विमोचन किया।

खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋणों की भुगतान तिथि बढ़ाई

जयपुर। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र

■ 2.19 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केन्द्रीय सहकारी बैंकों

द्वारा पैकस/लैम्पस के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी।



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से सचिवालय में विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के पार्श्वद के साथ अन्य लोगों ने मुलाकात कर उनके द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों के लिए उनको गुलदस्ता देकर धन्यवाद दिया।

21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कुल 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की तथा 4 अधिकारियों के विरुद्ध धारा 17-ए में भ्रष्टाचार के आरोपों की विस्तृत जांच/अनुसंधान की पूर्वानुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रदान की। सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4

■ 18 प्रकरणों का निस्तारण

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति

अधिकारियों को पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें से 2 प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का निर्णय किया गया। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के प्रमाणित पाये जाने से संबंधित अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय किया।



नारायण सिंह सर्किल पर रोडवेज बस स्टैंड बंद कर ट्रांसपोर्ट नगर पर करनेसे यहां गाड़िया नहीं रुक रही हैं। त्रिमूर्ति सर्किल की रेड लाइट पर गाड़ी कुछ ज्यादा ही समय के लिए रुकती है। मंगलवार को लोग बसों में बैठने के लिये नारायण सिंह सर्किल से त्रिमूर्ति सर्किल तक भागते नजर आए।

भजनलाल सरकार के 3 माह में 10 फीसदी एम.ओ.यू. उतरे धरातल पर : राजेंद्र राठौड़

जयपुर। राजिंज राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, मंत्री सुमित गोदारा, सुरेश सिंह रावत और भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने निरन्धीय बताया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने जूली के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जूली

विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं और यह आपका संवैधानिक दायित्व है कि राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएं। परंतु दुर्भाग्यवश, जूली अपनी जिम्मेदारियों से भटक कर केवल निराधार आरोप लगाने में व्यस्त हैं।

राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान इन्वेस्ट समिट

का आयोजन हुआ था। इसमें करीब साढ़े 12 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए थे, लेकिन वास्तविकता यह रही कि उनमें से सिर्फ 2 फीसदी ही धरातल पर उतर सका। जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के पहले ही वर्ष इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू किए।

इतना ही नहीं, भजनलाल शर्मा सरकार की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता की परिणाम है कि मात्र 3 महीने के भीतर करीब 10 प्रतिशत निवेश धरातल पर उतर चुका है। प्रत्येक एमओयू के क्रियान्वयन के लिए अलग से सक्षम अधिकारी की नियुक्ति के साथ स्वयं मुख्यमंत्री स्तर पर 3 माह में एमओयू

की निरंतर समीक्षा की जा रही है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार है जब किसी सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही राजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 30 से अधिक देशों के 5000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया। इसमें 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू हुए।

भाजपा में राष्ट्र प्रथम की भावना है : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को व्यापक रूप से मनाया जाएगा। प्रदेशभर में जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके राष्ट्र भक्त नागरिकों के साथ जुड़ने, पार्टी को समर्थन देने की अपील करेंगे। राठौड़ ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया

कि प्रत्येक राष्ट्र भक्त नागरिक 6 अप्रैल को अपने घरों पर भाजपा का झंडा फहराए, ताकि अराष्ट्रीय गतिविधियों में लिप्त लोगों को सही मार्ग पर लाया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक मात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्र को सशक्त बना सकती है, प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा कर सकती है और सर्वोपेक्ष विकास की भावना के

साथ कार्य करती है। भाजपा ही सर्वे भवतु सुखिने की भाजपा के साथ कार्य करती है।

मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा की सोच नेशन फर्स्ट की है। राष्ट्र प्रथम की सोच वाली भाजपा में दल बाद में आता है, और स्वयं को अंत में माना जाता है। जबकि अन्य पार्टियों में पहले स्वयं की भावना के साथ कार्य किया जाता है।

प्राइवेट बसों से वसूली करने वाले गिरोह के चार बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। झोटवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से प्राइवेट बसों से वसूली करने वाले गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध वसूली के 45



■ पुलिस ने अवैध वसूली के 45 हजार रुपये, डराने-धमकाने के लिए प्रयुक्त चाकू सहित एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की है

■ पूछताछ में सामने आया है कि पिछले 15 वर्षों से लगातार प्राइवेट बसों से वसूली की जा रही थी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपयुक्त जयपुर पश्चिम निवासी कुमार ने बताया कि झोटवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से प्राइवेट बसों से वसूली करने वाले गिरोह के भगवान सिंह (37) निवासी मकराना जिला डीडवाना कुचामन हाल करधनी जयपुर, श्याम वीर सिंह (29) निवासी नीमकाथाना जिला सीकर, विक्रम सैन उर्फ विककी

झोटवाड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से प्राइवेट बसों से वसूली करने वाले गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

उर्फ बोगी (40) निवासी हरमाड़ा जयपुर और दिलिप सिंह (54) निवासी रानोली जिला सीकर हाल हरमाड़ा जयपुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गैंग हर बस से सौ रुपए तक ले रही थी। पैसा नहीं देने पर गैंग के लोग जान से मारने की धमकी देते थे और चौमू पुलिसिया और सामोद के बीच रास्ते में मौका मिलते ही बसों पर हमला कर पत्थर फेंक देते। फिर बस चालक और खलासी के साथ मारपीट करते। यह पूरा गिरोह शिफ्ट के अनुसार काम कर रहा था। हर शिफ्ट में

अलग-अलग लोग काम करते। वहीं जांच में सामने आया कि यह गैंग पिछले 15 साल से चल रहा था और हर महीने 10 लाख रुपए तक वसूल लेता था। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त पश्चिम आलोक सिंचल ने बताया कि झोटवाड़ा थाना इलाके में स्थित चौमू पुलिसिया पर प्राइवेट बसों से अवैध वसूली से संबंधित एक गोपनीय सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम की ओर से गोपनीय रूप से रैकी और जांच

करवाई। इस दौरान पता चला कि गिरोह के सदस्य चौमू पुलिसिया पर रुकने वाली प्राइवेट बसों से पचास से सौ रुपये वसूलते हैं। पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। पैसा नहीं देने पर चौमू पुलिसिया से आगे सामोद के रास्ते में बस पर हमला कर देते हैं। यह गिरोह संगठित तौर पर कई सालों से काम कर रहा है। सभी प्राइवेट बस ड्राइवर और बस कंडक्टर इनसे घबराए हुए हैं। जांच में पुष्टि होने पर वसूली करने वाली गैंग को अलग-अलग जगहों से पकड़ा।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में होंगे विकास कार्य

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी यार्ड में विद्युत, मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों एवं संपर्क रोड के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से बादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलुवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर एवं श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग 12 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के कार्य किए जाएंगे। कोटपतली, सुभेपुर, सुरतगाढ़, कोटा, श्रीगंगानगर, नागौर और गोलुवाला मंडियों में लगभग 39 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा।



दूसरे दिन मंगलवार को बूढ़ी गणगौर की सवारी शाही लवाजमे के साथ परकोटे में निकली।

राजस्थान हाउस में इटालियन नहीं, राजस्थानी स्थापत्य कला की झलक दिखे : दिया कुमारी

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को निर्माण भवन में आयोजित प्रदेश की सड़क एवं विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भाग लिया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दिल्ली में निर्माणधीन राजस्थान हाउस को जीवन तस्वीर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में वहां सुस्त काम हुआ और इटालियन सामग्री ज्यादा दिखाई दे रही थी। इसमें राजस्थानी सामग्री का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, क्योंकि यह इटली का नहीं राजस्थान का हाउस

■ उपमुख्यमंत्री ने ली सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के नाम से देश की राजधानी में बनने वाले भवन में राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण कलाओं, राजस्थान की निर्माण सामग्री का उपयोग करके एक ऐसा भवन बनाया जा रहा है, जो देश और विदेश से आने वाले लोगों में प्रदेश की विरासत की अमिट छाप छोड़े। उपमुख्यमंत्री मंगलवार को निर्माण

भवन में आयोजित प्रदेश की सड़क एवं विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने उपमुख्यमंत्री की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए 200 फिट बाईपास सहित, जयपुर शहर की टैफिक समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना बनाने एवं उसे तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में चल रही विभिन्न रिंग रोड परियोजनाओं, ब्लैक स्पार्ट्स का निराकरण, दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे, अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कोरीडोर आदि की भी उन्होंने बिन्दुवार समीक्षा की।

उपमुख्यमंत्री ने सीआरआईएफ योजना, राजस्थान स्टेट हाईवे ऑथरिटी, आरएसआरडीसी, पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि पीएमजीएसवाई चतुर्थ के तहत प्रदेश की 1630 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिनके सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ राजस्थान स्टेट हाईवे ऑथरिटी के स्वीकृत 19 कार्यों में से 15 पूर्ण किए जा चुके हैं तथा शेष 4 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

